

भारत के राष्ट्रपति,  
श्री राम नाथ कोविन्द  
का  
संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण

नई दिल्ली, जनवरी 31, 2020

माननीय सदस्यगण,

1. 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूँ।
2. यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में, हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
3. चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबासाहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण,

4. भारत का संविधान, इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही, 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश के

12 करोड़ नागरिकों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।

5. हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमारा संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इसके साथ ही हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।

माननीय सदस्यगण,

6. मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।
7. मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।
8. संविधान द्वारा अपेक्षित इस दायित्व को निभाने के लिए, मैं संसद के हरेक सदस्य का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय सदस्यगण,

9. हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

माननीय सदस्यगण,

10. लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

- एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।
- एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा
- एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।

माननीय सदस्यगण,

11. ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, मेरी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।
12. वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है। Resolving Insolvency की रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से 52वें स्थान पर और Global Innovation रैंकिंग में देश 74वें से 52वें स्थान पर पहुंच गया है। Logistics Performance Index में भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Travel and Tourism Competitiveness रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।
13. अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतरराष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं।

माननीय सदस्यगण,

14. मेरी सरकार, **‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’** के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के

साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है।

माननीय सदस्यगण,

15. बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लोकसभा में कहा था कि- “एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं?”
16. आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय सदस्यगण,

17. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।

18. वर्ष 2018 के अंत में जम्मू-कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक Block Development Councils के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।
19. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए NAFED को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

माननीय सदस्यगण,

20. मेरी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने, देशवासियों की अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दायित्व भी।
21. देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

22. देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।
23. देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो। मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं।
24. पूज्य बापू ने स्वच्छता को ईश्वर की उपासना से बढ़कर बताया था। पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गांवों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

माननीय सदस्यगण,

25. आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। घर में पानी के न होने से हमारी बहनों-बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही, दूषित पानी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल रही हैं। इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी सरकार ने, देश के

सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की है।

माननीय सदस्यगण,

26. मेरी सरकार का सबका साथ - सबका विकास - सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।
27. देश के 112 जिलों को Aspirational District - आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गईं। इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं। मैं प्रत्येक आकांक्षी जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सदस्यगण,

28. दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को, दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2022 में ही

अरुणाचल प्रदेश के 'हलोगी' में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा।

29. इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में Gas Based Economy का आधार बनेगा।
30. पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

माननीय सदस्यगण,

31. देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही, देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण भी, अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

32. मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हुनर हाट के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख 65 हजार हुनरमंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की शिक्षा निर्बाध जारी रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी गयी है।
33. मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।

माननीय सदस्यगण,

34. मेरी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आशाओं-अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। आरक्षण में वृद्धि, कानूनी अधिकार में वृद्धि के साथ ही सरकार ने एक हजार से ज्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया है। बीते 5 वर्षों में हजारों कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को e-Unique Identification Card जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक विशेष प्रयास शुरू किया था Indian Sign Language Dictionary का। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 6 हजार शब्दों की एक विशेष डिक्शनरी बनाई जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण,

35. भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।” पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय सदस्यगण,

36. हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है। हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।
37. मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूँ।

माननीय सदस्यगण,

38. मेरी सरकार यह पुनः स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो

प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

39. माननीय सदस्यगण,

भारतभूमि के महान संत कवि, थिरुवल्लुवर ने कहा था –

‘उरुवार उलगत्तार्क आणिअः ताट्राद, एरुवारै एल्लाम् पोरुत्त’

अर्थात्, “किसान, धुरी की कील के समान है जो पूरे विश्व को संभालकर रखता है। वह उन सबके भार का वहन करता है जो खेती नहीं कर सकते।”

40. हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा आय केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

41. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है।

42. मेरी सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए MSP में लगातार की गई

वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सदस्यगण,

43. मेरी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है। क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम हो रहा है। शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहद का निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है।
44. नए मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन, दोनों को दोगुना करने का लक्ष्य है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

45. प्राकृतिक आपदा से किसान को राहत दिलाने के लिए मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।
46. किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि e-NAM का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1 करोड़ 65 लाख किसान एवं

करीब सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90 हजार करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में e-NAM को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है।

माननीय सदस्यगण,

47. व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश, दोनों के विकास पर पड़ता है। मेरी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर, हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं।
48. आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

49. मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।
50. मेरी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की

लगभग 16 हजार MBBS और 4 हजार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 AIIMS की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।

51. मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार ने सिर्फ एक रुपये में 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की भी शुरुआत की है।

माननीय सदस्यगण,

52. मेरी सरकार के प्रयासों से, महिला उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की अनुमति दी गई है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

53. मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए

जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसके लिए देशभर में 1 हजार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि Women Help Desk का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है।

माननीय सदस्यगण,

54. 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है और सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में युवा लीडरशिप तैयार करने पर भी है। इस दशक में रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र का नेतृत्व हमारे देश के युवा ही करेंगे। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का लाभ युवा शक्ति को निरंतर मिल रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हजार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों में देश में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
55. स्किल इंडिया अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए जरूरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

56. मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और Innovation को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही है। Higher Education Funding Agency –

HEFA के माध्यम से देश के 75 शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7 हजार और उच्च शिक्षा में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 'स्वयं 2' की शुरूआत भी की गई है।

57. मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।

माननीय सदस्यगण,

58. खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना हमारे युवाओं में है। खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक पोडियम स्कीम सहित अनेक योजनाओं के तहत, युवा टैलेंट की पहचान की जा रही है, उन्हें उच्च स्तर पर मुकाबले के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।

माननीय सदस्यगण,

59. इस वर्ष एक अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की सौवीं पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाला कालजयी आह्वान किया था। स्वराज की सिद्धि के बाद देश ने सुराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सुराज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेरी सरकार तीन स्तरों पर कार्य कर रही है:

- पहला- सरकार की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन तथा संगठनों का सशक्तीकरण,

- दूसरा- पारदर्शिता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल,
- और तीसरा- जमीनी स्तर पर स्वस्थ स्पर्धा और जनभागीदारी को बढ़ावा।

माननीय सदस्यगण,

60. “Minimum Government, Maximum Governance” के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक Reform किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में Reform किया जा रहा है। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है।

माननीय सदस्यगण,

61. योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए Silos का समाप्त होना और विभागों में समन्वय बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले वर्ष अक्टूबर में सिविल सेवा की 20 से अधिक सेवाओं के अफसरों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल ही में भारतीय रेल के प्रबंधन को भी पुनर्गठित किया गया है। देश के अलग-अलग ट्राइब्यूनल्स और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसके लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को भी सुधारा जा रहा है। योजनाओं को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया है। सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय एवं जलशक्ति मंत्रालय का गठन इसी सोच का उदाहरण है।

माननीय सदस्यगण,

62. सरकारी सेवाओं और सरकारी लाभ की तेज और सटीक डिलिवरी मेरी सरकार की विशेषता रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर सुशासन का आधार बनाया गया है। पारदर्शिता के साथ

लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के बैंक खाते में शत प्रतिशत राशि का ट्रांसफर और योजनाओं की मॉनीटरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया है। अब इस दशक में यही टेक्नोलॉजी, देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी उनकी मदद करेगी।

माननीय सदस्यगण,

63. हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति Industry 4.0 का आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है। मेरी सरकार द्वारा 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से Digital Access, Digital Inclusion और Digital Empowerment पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। देश को इस बात पर गर्व है कि पिछले पाँच वर्षों में भारत में विकसित हुई डिजिटल व्यवस्थाएं, विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

माननीय सदस्यगण,

64. आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास Rupay कार्ड है। दिसंबर 2019 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। हाल ही में सरकार ने BHIM App का नया वर्जन भी लॉन्च किया है।

65. JAM यानि जनधन-आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा अपनी लगभग 450 योजनाओं को DBT-डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा जा चुका है। DBT के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

66. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानि GeM ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है। GeM से छोटे और लघु उद्यमियों को जहां सरकार के रूप में बहुत बड़ा बाजार मिला है वहीं इससे सरकार की पहुंच सीधे उद्यमी तक हुई है। पिछले तीन साल में सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा GeM के माध्यम से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है।
67. टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। अब हम इनकम टैक्स विभाग में भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां मानव दखल यानि ह्यूमन इंटरफेस न हो। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स विभाग की कार्यसंस्कृति में बड़ा सुधार आएगा।

माननीय सदस्यगण,

68. शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है। इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन सेंटरों के माध्यम से सरकार अपनी 45 से ज्यादा सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रही है।

माननीय सदस्यगण,

69. एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करते हुए मेरी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व संगठित व्यवस्था विकसित कर रही है।
70. देश में Seamless Mobility सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन पहले One Nation, One FasTag लॉन्च किया गया है। One Nation One Mobility Card के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में, यातायात के अलग-अलग माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विकसित हुई है। सरकार

द्वारा One Nation, One Ration Card की शुरुआत भी की जा रही है। One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है।

माननीय सदस्यगण,

71. भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के बीच विकास की योजनाओं में स्पर्धा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनुभव का लाभ दूसरे राज्यों को भी दें। मेरी सरकार इसलिए Competitive Cooperative Federalism - प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर निरंतर बल देती रही है। सरकार द्वारा राज्यों को, जिला और गांव के स्तर पर Real Time Data से मिलने वाली रैकिंग प्रदान की जा रही है। इसका प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, Ease of Doing Business तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर Aspirational District Programme तक में नजर आता है।
72. सरकारें सही योजनाएं बना सकें और लक्ष्य केंद्रित कार्य कर सकें इसके लिए Census से मिली जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Census में इस बार यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसलिए जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
73. डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच मेरी सरकार निजता के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार संसद में Data Protection Bill लेकर आई है।

माननीय सदस्यगण,

74. मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टैकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच FDI 3 अरब डॉलर बढ़ा है।
75. वहीं, पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंकों के विलय से बैंक सुदृढ़ हुए हैं और ऋण देने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।

माननीय सदस्यगण,

76. अर्थव्यवस्था की गति एवं मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार मेक इन इंडिया को सशक्त कर रही है। सरकार द्वारा तमिलनाडु और यूपी में दो डिफेंस कॉरिडोर और देश में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

77. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग में भारत विशेष रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मैन्युफेक्चरिंग को और गति देने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है। वर्ष 2014-15 में देश में जहां करीब 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 4 लाख 58

हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

माननीय सदस्यगण,

78. आजादी के मूलमंत्र में एक भावना थी- आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब हर भारतीय, भारत में बनी हर वस्तु पर गर्व करे। मेरी सरकार 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' के मंत्र पर विश्वास करती है। मैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से, देश की हर सरकार से आग्रह करता हूं कि 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' को एक आंदोलन में परिवर्तित करें। मैं प्रत्येक भारतीय से भी आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।

माननीय सदस्यगण,

79. देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे। कनेक्टिविटी पर विशेष बल देते हुए, नए हाईवेज, नए वाटरवेज, नए एयरवेज, नए आईवेज के निर्माण पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
80. देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए देश के कोने-कोने तक ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है। इन सड़कों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें स्कूल, अस्पताल व मंडियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू

किया गया है। इसके तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा।

81. सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे -2 के जरिए असम के पांडू तक कार्गो कंटेनर पहुंचा है। इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल और फरक्का पर नैविगेशन लॉक पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो भी चलाये जा सकें।
82. शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और NCR के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है।

माननीय सदस्यगण,

83. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहर, एक नई भूमिका के साथ उभर रहे हैं। स्वच्छता हो, सुविधाएं हों, स्टार्ट अप हों या फिर दूसरा कारोबार, छोटे शहरों की प्रगति उत्साहवर्धक है। साल 2014 के बाद से ही छोटे शहरों में स्टार्ट-अप्स की 45 से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है। इसी तरह उड़ान योजना के तहत करीब 35 लाख लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 335 नए हवाई मार्गों की अनुमति दी गयी है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में, देश का आधे से ज्यादा डिजिटल लेन-देन इन्हीं टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में होगा।

84. छोटे शहरों और नए मध्यम वर्ग के विकास को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा उनकी अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने से भी सबसे अधिक लाभ छोटे शहरों के मध्यम वर्ग को हुआ है। मध्यम वर्ग के जिन परिवारों की आय 18 लाख रुपए तक की है, उन्हें 20 वर्ष तक के होमलोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। घरों को बनाने की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की जो व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलेगा।

माननीय सदस्यगण,

85. Clean energy के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अब देश के 407 जिलों में विस्तार किया जा रहा है। अब हम Gas Based अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

86. मेरी सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम के दूसरे चरण में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है।

माननीय सदस्यगण,

87. देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है।

88. वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के 102 शहरों में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लागू करने जा रही है। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।
89. इन सारे प्रयासों का असर देश के पर्यटन क्षेत्र पर भी दिख रहा है। बीते कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। हाल में देश की हैरिटेज बिल्डिंग्स के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कोलकाता से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से तैयार हो रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पर्यटन सेक्टर को मजबूती मिल रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सरदार पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या भी नित नए रिकॉर्ड बना रही है।

माननीय सदस्यगण,

90. देश की विरासत के संरक्षण और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करने को मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग मानती है। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में हमारी आदिवासी वीरांगनाओं एवं वीरों के सशक्त योगदान को समर्पित म्यूजियम्स का निर्माण, देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महान समाज सुधारक और देश को दिशा दिखाने वाले राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती भी भव्यता के साथ मनाई जाएगी।

माननीय सदस्यगण,

91. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में

टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। ISRO द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम-गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।

माननीय सदस्यगण,

92. बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। Chief of Defence Staff - CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे तीनों सेनाओं में समन्वय भी बढ़ेगा और सेनाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज़ होगी।
93. भारत की सेनाओं और सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण तथा बुलेट प्रूफ जैकेट हों, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक रायफल AK 203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जब तेजस के Naval Prototype ने INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग की और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठा था। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

माननीय सदस्यगण,

94. मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है ये जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद

फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार के निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है।

माननीय सदस्यगण,

95. मेरी सरकार विदेश नीति को, देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू मानती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास और संपन्नता को गति दे रहे हैं। “Neighbourhood First” की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं।
96. भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI यानी Coalition on Disaster Resilient Infrastructure नाम की वैश्विक साझेदारी की पहल की है। आपदा से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से एक संवेदनशील विश्व शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और सशक्त होने जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

97. जो दशक अभी शुरू हो रहा है, वह आने वाले समय में, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
98. देशहित के लिए देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तथा यह कर्तव्य बोध हमारे नागरिक जीवन की प्राथमिकता

बने, इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए। आइए, हम सब 2020 के दशक को कर्तव्यों का दशक बनाएं।

99. हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है।
100. मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे।
101. आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं।

जयहिंद !!!

\*\*\*\*\*